foreigners by way of allowing commissions and other kinds of concessions;

(b) if so, the steps proposed to be taken to save the Corporation from this disadvantage; and

(c) whether Government propose to nationalize the Coir export trade?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). Export of Coir products can be made by registered exporters including state trading agencies *e.g.* Kerala State Coir Corporation after obtaining an export licence from Coir Board. With a view to have healthy competition among the exporters, export licence is issued only when the contract is at minimum floor price fixed by the Coir Board or at higher price.

(c) There is no such proposal at present.

भारत द्वारा चीजों का आयात

9840. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष की अपेक्षा जो चीजें भारत ने इस वर्ष आयात की हैं उन पर अलग अलग कितना बढ़ाकर दाम देना पड़ेगा;

(ख) इस वर्ष भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात होगा उन पर अलग अलग कितना मूल्य बढ़ा कर बेचा जाएगा;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अन्तर रहेगा; और

(घ) इस विदेशी मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). यद्यपि हमारे निर्यात और आयात दोनों प्रकार के उत्पादों की कीमतों में सामान्यत: विश्व-व्यापी हो रही है लेकिन तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि से और अन्य आवश्यक आयातों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होने से वर्ष 1974–75 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा भारत के विदेश व्यापार का घाटा और बढ़ जाने की सभावना है ।

विश्व बाजार में व्यापारिक स्थिति अधिकाधिक अनिश्चित होती जा रही है । फिर भी व्यापार के घाटे को यथासंभव कम करने के लिए सभी देशों के लिए, जिन में खाड़ी क्षेत्र के तेल उत्पादक देश शामिल हैं निर्यात का क्रैश प्रोग्राम रखा है ।

कार्यक्रम की प्रधान बात निम्नलिखित हैं :—

(क) निकटतम भविष्य में अधिकतम निर्यात संभाव्यता वाले उत्पादों का पता लगाना ।

(ख) ऐसे गन्तव्य स्थलों का पता लगाना जहां इन उत्पादों के निर्यातों से अधिक इकाई मूल्य प्राप्त हो सकेगा; और

(ग) ऐसे उपाय ढूंढना जिनसे स्वदेशी उत्पादन आधार संवर्धित होगा और इन उत्पादों के निर्यात के लिए अतिरिक्त देशी निर्यात माल जुटाया जायेगा ।

क्रैश प्रोग्राम के परिणामस्वरूप ऐसी आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 7·6% की जो दर रखी गई है उसके मुकाबले में चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात काफी अधिक होंगे । तेल उत्पादक देशों को, जिनमें फारस की खाड़ी का क्षेत्र भी सम्मिलित है, जो निर्यात होंगे उनके बारे में ऐसी सभावना है कि वे 1974–75 में 1972–73 के स्तर की तुलना में दुगने से भी अधिक होंगे ।